भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

***

फरवरी, 2022 के लिए मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय, संविधान के 73वें संशोधन की निगरानी और कार्यान्वयन, परामर्शी कार्य के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक बुनियादी ढाँचा, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपर्युक्त उद्देश्य को साकार करने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना और परामर्शी कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरण और समग्र योजना।

माह के दौरान निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ थी:

1. माह के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय की सिफ़ारिश पर वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान और सिक्किम राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए क्रमश: 570.80 करोड़ रुपए और 6.20 करोड़ रुपए की धनराशि के रूप में मूल (अबद्ध) अनुदान की दूसरी किस्त और गोवा को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 11.00 करोड़ रुपये के मूल (अबद्ध) अनुदान की पहली किस्त जारी की है।

2. अब तक, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों/पारंपरिक स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव सहित घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन, आदि बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए 15वां वित्त आयोग अनुदान की 26,532.58 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

3. भारत और विदेशों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के सुधार के लिए उनके विभिन्न कार्यक्रमों पर विश्व बैंक, भारत क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दिनांक 01.02.2022

को आयोजित की गई थी। बैठक में ग्रामीण विकास के लिए मंत्रालय के कार्यक्रमों में विश्व बैंक को जोड़ने की विभिन्न संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

4. सरकार और आईआईटी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के सहयोग से विकसित स्मार्ट ई-वेंडिंग कार्ट के वित्तपोषण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए 15 फरवरी, 2022 को एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पीएसए, आईआईटी, एसबीआई और अन्य वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

5. एनआईआरडीपीआर द्वारा 23-25 फरवरी, 2022 के दौरान राष्ट्रीय वॉश कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जिसमें सचिव, पंचायती राज ने समापन सत्र में वाश कॉन्क्लेव के प्रतिभागियों को संबोधित किया।

6. श्री के.एस. सेठी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने "सफलताएं, बाधाएं और आगे का रास्ता: एसबीएम -2 प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पीआरआई द्वारा वित्तपोषण और व्यय में सुधार" विषय पर पैनल चर्चा में भाग लिया।

7. 'स्वामित्व' योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से त्रिपुरा स्वायत्त जिला परिषद, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद और असम के कार्बी आंगलांग सहित 29 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना में शामिल हैं। इस योजना के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो इस योजना के तहत विषयगत प्रभाव वाले क्षेत्रों का चार्ट तैयार करने, सर्वोत्तम प्रथाओं और भविष्य के कार्यों के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए क्षेत्र से विषय विशेषज्ञों और चिकित्सकों को आकर्षित करती है। विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 21 फरवरी, 2022 को हुई। इसके अलावा, बजट के बाद के वेबिनार में योजना पर चर्चा की गई थी, जिसका विषय 'लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड' - एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण के माध्यम से भूमि शासन को आसान बनाना था। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ नियमित बैठकें (वर्चुअल कॉन्फ्रेंस) भी आयोजित की गईं। अब तक 1,12,879 गांवों में ड्रोन उड़ान और 104 जिलों के सभी आबाद गांवों में ड्रोन-सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है।

8. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन के लिए, मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों को सख्ती से राजी कर रहा है। इस

संबंध में, मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत पंजीकरण के लिए राज्यों से अनुरोध कर रहा है। चालू वर्ष यानी 2021-22 में 84% ग्राम पंचायतों ने अपनी मंथ बुक बंद कर दी हैं।

9. 2,31,787 पंचायती राज संस्थाओं ने ई-ग्राम स्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) को ऑन-बोर्ड किया है। फरवरी 2022 माह में 1,93,603 पंचायती राज संस्थाओं ने XV वित्त आयोग अनुदान किए गए व्यय के लिए eGSPI का उपयोग करके ऑनलाइन लेनदेन किया है।

10. इसके अलावा, पीआरआई स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने हेतु मंत्रालय ई-ग्रामस्वराज में रसीद प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से कैप्चर करने के लिए 'पीएफएमएस के साथ राज्य ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन' की प्रक्रिया में है। 23 राज्यों ने स्टेट ट्रेजरी सिस्टम के रिवर्स इंटीग्रेशन की इस कवायद को पूरा कर लिया है ।

11. पंचायत खातों की ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए, वर्ष 2019-20 के लिए, 27 राज्यों (केरल सहित) ने पहले ही 7,781 लेखापरीक्षकों, 2,53,884 लेखापरीक्षितियों को पंजीकृत कर लिया है और 14वें वित्त आयोग के खातों की लेखापरीक्षा के लिए 1,31,355 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा योजना तैयार की है। आवेदन पर राज्यों द्वारा 11,34,691 टिप्पणियां दर्ज की गई हैं और वर्ष 2019-20 के लिए 1,05,040 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 1,55,486 ग्राम पंचायतों, 1,746 बीपी और 107 जिला पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई है। राज्यों द्वारा 9,05,741 अवलोकन दर्ज किए गए हैं और कुल 70,880 लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं, जिनमें से 69,488 ग्राम पंचायतों द्वारा, 1334 बीपी द्वारा और 58 जिला पंचायतों द्वारा तैयार की गई हैं।

12. आरजीएसए स्कीम के तहत राज्य के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के लिए असम राज्य को 29.9182 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

13. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास को सुदृढ़ करने के लिए, इस मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ कई अंतर-मंत्रालयी बैठकों का आयोजन किया है। फरवरी में, दिनांक 10.02.2022 से 16.02.2022 तक कई मंत्रालयों / विभागों के साथ ऐसी छह बैठकें आयोजित की गई हैं।

14. दिनांक 18.01.2022 को हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक की सिफारिशों के आधार पर, संशोधित आरजीएसए स्कीम पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के लिए मसौदा नोट को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए दिनांक 21.02.2022 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से परिचालित किया गया है।

15. एसडीजी के स्थानीयकरण की दिशा में मंत्रालय की रणनीति के भाग के रूप में असम, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ बाल-हितैषी ग्राम पंचायत और गांव में इंजीनियरिंग के विकास के दो विषयगत क्षेत्रों हेतु 28 फरवरी, 2022 को पहली आभासी क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

16. पीआरआई के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण और राज्यों की भूमिका जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 24.02.2022 को दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी के साथ विभागों में राज्य पंचायती राज मंत्रियों और सचिवों के साथ संवादात्मक बैठकों की श्रृंखला में पहली बैठक आयोजित की गई। इससे योजना के कार्यान्वयन पर स्थिति का आकलन, पंचायत के बुनियादी ढांचे का प्रावधान, पंचायत का डिजिटलीकरण और समय पर अन्य जीवंत ग्राम सभाओं को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायत और पंचायत संघ, तमिलनाडु सरकार बैठक में शामिल हुए क्योंकि अन्य का प्रतिनिधित्व उनके सचिवों द्वारा किया गया था।

17. 1 फरवरी 2022 तक मंत्रालय के पास 113 शिकायतें/याचिकाएं लंबित थीं और फरवरी माह के दौरान 285 (अर्थात 262 ऑनलाइन + 23 भौतिक) शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। कुल 398 (फरवरी में प्राप्त 285 + पिछले महीने से 113 अग्रेषित) में से 321 शिकायतों / याचिकाओं का फरवरी में निपटारा किया गया और 77 शिकायतें 1 मार्च, 2022 को आगे लाई गई।

18. फरवरी, 2022 के दौरान, ई-ऑफिस सिस्टम में 102 ई-फाइलें खोली गईं, जो महीने के दौरान खोली गई कुल फाइलों का 100% है।

Government of India

Ministry of Panchayati Raj

***

Monthly Summary for the month of February, 2022

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realize the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work.

The following were the main activities during the month:

1. During the month, on the recommendation of Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Finance has released 2nd installment of Basic (Untied) Grants for F.Y. 2021-22 for Rural Local Bodies to the State of Rajasthan and Sikkim amounting to Rs. 570.80 crore and Rs. 6.20 crore respectively and 1st installment of Basic (Untied) Grants of Rs.11.00 crore for FY 2021-22 to Goa.

2. As on date, XV FC grants to the tune of Rs. 26,532.58 crore for FY 2021-22 has been released by the Ministry of Finance to the States for Rural Local Bodies/Traditional Local Bodies for improving basic services including supply of drinking water, rain water harvesting, water recycling, sanitation & maintenance of ODF status including management and treatment of household waste, human excreta and faecal sludge management, etc.

3. A meeting with representative from World Bank, India Regional office on their various interventions for improvement of rural local bodies in India and abroad was

held on 01.02.2022. The meeting also deliberated on various possibilities of associating World Bank in Ministry's programmes for rural development.

4. A VC meeting was held on 15th February, 2022 to discuss various aspects of financing Smart e–Vending Carts developed in association with Principal Scientific Adviser (PSA) to Government and IITs. Representatives from PSA, IITs, SBI and other financial institutions participated in the meeting.

5. The National WASH Conclave was organized by NIRDPR during 23-25, February, 2022 in which Secretary, Panchayati Raj addressed the participants of the WASH Conclave in the concluding session.

6. Shri K. S. Sethi, Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj participated in panel discussions on the subject of "Successes, Bottlenecks and Way forward: Improving financing and spending by PRIs for fulfilling SBM-2 Priorities".

7. Under the SVAMITVA Scheme, with the aim to provide the 'Record of Rights' to village household owners in inhabited rural areas and issuance of Property cards to the Property owners, 29 States/UTs are on-boarded on Scheme including Autonomous District Council of Tripura, Bodoland Territorial Council and Karbi Analog of Assam. An Expert Committee has been constituted under the Scheme drawing in subject matter experts and practitioners from the field to chart out the thematic impact areas under the Scheme, best practices and provide recommendations for future course of action. First meeting of the Expert Committee held on 21stFeb, 2022. Furthermore, Scheme was discussed in post budget webinar on 'Leaving No Citizen Behind'- Easing land governance through end-to-end digitisation. Regular meeting (VCs) with States and SoI for implementation of Scheme in all States/UTs were also held. **Till now, drone flying has been completed in 1,12,879 villages and drone-survey completed in all inhabited villages of 104 districts.**

8. For management of finances available to Panchayats from various sources, the Ministry has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been pursuing States

for closure of account on eGramSwaraj as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS. In the current year i.e. 2021-22, 84% GPs have closed their month books.

9. 2,31,787 PRIs have on-boarded eGramSwaraj-PFMS Interface (eGSPI). In the month of February 2022- 1,93,603 PRIs have transacted online using eGSPI for the expenditure incurred XV Finance Commission Grant.

10. Further, strengthening the accountability and transparency at the PRI level; the Ministry is in the process of 'Reverse Integration of State Treasury system with PFMS' to capture the receipt entries automatically in eGramSwaraj. 23 States have completed this exercise of reverse integration of State treasury system.

11. For AuditOnline of Panchayat accounts, for the year 2019-20, 27 States (including Kerala) have already registered 7,781 Auditors, 2,53,884 Auditees and prepared Audit Plans of 1,31,355 GPs for Auditing 14th Finance Commission accounts. 11,34,691 observations have been recorded by States on the application and 1,05,040 audit reports have generated for the year 2019-20. For the year 2020-21, audit plans have been prepared by 1,55,486 GPs, 1,746 BPs and 107 ZPs. 9,05,741 observations have been recorded by States and total 70,880 audit reports have been generated out of which 69,488 by GPs, 1334 by BPs and 58 by ZPs generated.

12. Funds to the tune of Rs.29.9182 Cr has been released to State of Assam under the scheme of RGSA towards the approved AAP of the state.

13. In order to reinforce a collaborative endeavour for Localizing SDGs through PRIs, this Ministry has been engaging with various Ministries/Departments by holding a series of Inter-Ministerial meetings. In February, six such meetings have been conducted with as many Ministries/Departments from 10.02.2022 to 16.02.2022.

14. Based on the recommendations of Expenditure Finance Committee (EFC) at its meeting on 18.01.2022, draft Note for Cabinet Committee on Economic Affairs on

the revamped RGSA scheme has been circulated vide OM dated 21.02.2022 for inter-ministerial consultation.

15. As part of Ministry's strategy to take forward the Localization of SDGs, the first virtual regional workshop with the States of Assam, Meghalaya, Odisha, Tripura and West Bengalon two thematic areas of Child-Friendly Gram Panchayat and Engendering Development in Village was held on 28th February, 2022.
16. The first meeting in the series of interactive meetings with State Panchayati Raj Ministers and Secretaries in the Departments held with southern States and UTs of Lakshadweep and Puducherry on 24.02.2022 to discuss various issues like localisation of sustainable development goals through PRIs and role of the States, status taking on the implementation of SVAMITVA scheme, provision of panchayat infrastructure, digitalization of Panchayat and promotion of timely and vibrant Gram Sabhas. The Minister of Rural Development, Panchayat and Panchayat Unions, Government of Tamil Nadu joined the meeting as others were represented by their Secretaries.

17. There were 113 grievances/petitions pending with Ministry as on 1st February, 2022 and 285 (i.e. 262 online + 23 physical) grievances/ petitions were received during the month of February. Out of total 398 (285 received in February + 113 carried forward from last month), 321 grievances/petitions were disposed in February and 77 were carried forward as on 1st March, 2022.

18. During February 2022, 102 e-files were opened in e-office system which constitutes 100% of the total files opened during the month.

****